Ministry of Finance

Period of Analysis: 25/06/2026 to 25/06/2026

Dossier Name: Ministry of Finance

Dossier Created On: 25/06/2026

सत्यमेव जयते

वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF
FINANCE

वित्त मंत्रालय

अखिल भारतीय सिविल लेखा (वरिष्ठ लेखाधिकारी) संगठन ने आठवें वेतन आयोग के समक्ष रखीं केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों की मांगें

प्रविष्टि तिथि: 24 JUN 2026 5:30PM by PIB Lucknow

अखिल भारतीय सिविल लेखा (वरिष्ठ लेखाधिकारी) संगठन (AICAOA) के प्रतिनिधिमंडल ने आज लखनऊ में आयोजित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (CCAS) अधिकारियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों एवं मांगों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।संगठन ने आयोग का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि केंद्रीय सिविल लेखा सेवा का ऐतिहासिक रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) संगठन के साथ समान दर्जा एवं वेतन संरचना रही है। इसके अतिरिक्त, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम तथा सप्तम वेतन आयोगों द्वारा विभिन्न लेखा संगठनों के लिए समान वेतनमान एवं सेवा शर्तों की संस्तुति किए जाने के बावजूद केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों के वेतनमान एवं पदानुक्रम में उल्लेखनीय विसंगतियां बनी हुई हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के समक्ष यह भी रेखांकित किया कि भारत सरकार की समस्त प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेखांकन तथा वित्तीय प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी केंद्रीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा निभाई जाती है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी इस संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण सेवा को आवश्यक सेवाओं (Essential Services) के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसके बावजूद सेवा की ऐतिहासिक स्थिति एवं महत्व के अनुरूप वेतन एवं कैडर संरचना का संरक्षण नहीं हो पाया है।संगठन ने आयोग से अनुरोध किया कि इन दीर्घकालिक विसंगतियों को दूर करते हुए केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों को उनकी ऐतिहासिक समानता, दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के अनुरूप उचित वेतनमान एवं सेवा स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की जाए।

संगठन की ओर से अध्यक्ष श्रीमती गीतांजलि, महासचिव श्री कौशल मिश्रा तथा विधि समिति के अध्यक्ष श्री यू. सी. जोशी ने आयोग के समक्ष अत्यंत सशक्त एवं तथ्यपरक ढंग से पक्ष प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि आयोग केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों की न्यायोचित मांगों पर सकारात्मक विचार करेगा।उल्लेखनीय है कि आठवां केंद्रीय वेतन आयोग 22-23 जून 2026 को लखनऊ में विभिन्न कर्मचारी संगठनों एवं हितधारकों से परामर्श कर रहा है।

***

(रिलीज़ आईडी: 2277475) आगंतुक पटल : 176

Downloaded from
SAMVAD 2.0

Sr. No.	Headline	Publication	Edition	Page No.	Date
1	All India Civil Accounts (Senior Accounts Officer) Organization presented demands of Central Civil Accounts Service Officers before the Eighth Pay Commission	Choice Times	Lucknow	3	25/06/2026
2	Demands of Central Civil Accounts Service Officers presented by All India Civil Accounts (Senior Accounts Officer) Organization before the Eighth Pay Commission	Ek Sandesh	Lucknow	8	25/06/2026
3	All India Civil Accounts (Senior Accounts Officer) Organization presented demands of Central Civil Accounts Service Officers before the Eighth Pay Commission	General Force	Lucknow	3	25/06/2026
4	Demands of Central Civil Accounts Service Officers Presented Before Eighth Pay Commission	Haar Baat	Lucknow	4	25/06/2026
5	All India Civil Accounts (Senior Accounts Officer) Organization presented demands of Central Civil Accounts Service officers before the Eighth Pay Commission.	Prabhat Khabar	Lucknow	2	25/06/2026
6	All India Civil Accounts (Senior Accounts Officer) Organization presented demands of Central Civil Accounts Service officers before the Eighth Pay Commission	Sahara Jeewan	Lucknow	8	25/06/2026
7	Demands of Central Civil Accounts Service Officers Placed Before Eighth Pay Commission	Voice of Basti	Lucknow	1	25/06/2026

Publication Name: Choice Times

Publication Date: 25/06/2026

Edition: Lucknow

Page No: 3

CCM: 963.88

All India Civil Accounts (Senior Accounts Officer) Organization presented demands of Central Civil Accounts Service Officers before the Eighth Pay Commission

अखिल भारतीय सिविल लेखा (वरिष्ठ लेखाधिकारी) संगठन ने आठवें वेतन आयोग के समक्ष रखीं केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों की मांगें

लखनऊ। अखिल भारतीय सिविल लेखा (वरिष्ठ लेखाधिकारी) संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने आज लखनऊ में आयोजित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों एवं मांगों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। संगठन ने आयोग का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि केंद्रीय सिविल लेखा सेवा का ऐतिहासिक रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संगठन के साथ समान दर्जा एवं वेतन संरचना रही है। इसके अतिरिक्त, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम तथा सप्तम वेतन आयोगों द्वारा विभिन्न लेखा संगठनों के लिए समान वेतनमान एवं सेवा शर्तों की संस्तुति किए जाने के बावजूद केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों के वेतनमान एवं पदानुक्रम में उल्लेखनीय विसंगतियां बनी हुई हैं। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के समक्ष यह भी रेखांकित किया कि भारत सरकार की समस्त प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेखांकन तथा वित्तीय प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी केंद्रीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा निभाई जाती है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी इस संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण सेवा को आवश्यक सेवाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसके बावजूद सेवा की ऐतिहासिक स्थिति एवं महत्व के अनुरूप वेतन एवं कैडर संरचना का संरक्षण नहीं हो पाया है। संगठन ने आयोग से अनुरोध किया कि इन दीर्घकालिक विसंगतियों को दूर करते हुए केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों को उनकी ऐतिहासिक समानता, दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के अनुरूप उचित वेतनमान एवं सेवा स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की जाए। संगठन की ओर से अध्यक्ष श्रीमती गीतांजलि, महासचिव श्री कौशल मिश्रा तथा विधि समिति के अध्यक्ष श्री यू. सी. जोशी ने आयोग के समक्ष अत्यंत सशक्त एवं तथ्यपरक ढंग से पक्ष प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि आयोग केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों की न्यायोचित मांगों पर सकारात्मक विचार करेगा। उल्लेखनीय है कि आठवां केंद्रीय वेतन आयोग 22-23 जून 2026 को लखनऊ में विभिन्न कर्मचारी संगठनों एवं हितधारकों से परामर्श कर रहा है।

Publication Name: Ek Sandesh
Publication Date: 25/06/2026
Edition: Lucknow
Page No: 8
CCM: 1176.8

Demands of Central Civil Accounts Service Officers presented by All India Civil Accounts (Senior Accounts Officer) Organization before the Eighth Pay Commission

अखिल भारतीय सिविल लेखा (वरिष्ठ लेखाधिकारी) संगठन ने आठवें वेतन आयोग के समक्ष रखीं केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों की मांगें

लखनऊ। अखिल भारतीय सिविल लेखा (वरिष्ठ लेखाधिकारी) संगठन (AICAOA) के प्रतिनिधिमंडल ने आज लखनऊ में आयोजित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (CCAS) अधिकारियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों एवं मांगों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।संगठन ने आयोग का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि केंद्रीय सिविल लेखा सेवा का ऐतिहासिक रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) संगठन के साथ समान दर्जा एवं वेतन संरचना रही है। इसके अतिरिक्त, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम तथा सप्तम वेतन आयोगों द्वारा विभिन्न लेखा संगठनों के लिए समान वेतनमान एवं सेवा शर्तों की संस्तुति किए जाने के बावजूद केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों के वेतनमान एवं पदानुक्रम में उल्लेखनीय विसंगतियां बनी हुई हैं।प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के समक्ष यह भी रेखांकित किया कि भारत सरकार की समस्त प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेखांकन तथा वित्तीय प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी केंद्रीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा निभाई जाती है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी इस संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण सेवा को आवश्यक सेवाओं (Essential Services) के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसके बावजूद सेवा की ऐतिहासिक स्थिति एवं महत्व के अनुरूप वेतन एवं कैडर संरचना का संरक्षण नहीं हो पाया है।संगठन ने आयोग से अनुरोध किया कि इन दीर्घकालिक विसंगतियों को दूर करते हुए केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों को उनकी ऐतिहासिक समानता, दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के अनुरूप उचित वेतनमान एवं सेवा स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की जाए। संगठन की ओर से अध्यक्ष गीतांजलि, महासचिव कौशल मिश्रा तथा विधि समिति के अध्यक्ष यू. सी. जोशी ने आयोग के समक्ष अत्यंत सशक्त एवं तथ्यपरक ढंग से पक्ष प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि आयोग केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों की न्यायोचित मांगों पर सकारात्मक विचार करेगा।उल्लेखनीय है कि आठवां केंद्रीय वेतन आयोग 22-23 जून 2026 को लखनऊ में विभिन्न कर्मचारी संगठनों एवं हितधारकों से परामर्श कर रहा है।

Publication Name: General Force
Publication Date: 25/06/2026
Edition: Lucknow
Page No: 3
CCM: 1144.48

All India Civil Accounts (Senior Accounts Officer) Organization presented demands of Central Civil Accounts Service Officers before the Eighth Pay Commission

अखिल भारतीय सिविल लेखा (वरिष्ठ लेखाधिकारी) संगठन ने आठवें वेतन आयोग के समक्ष रखीं केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों की मांगें

लखनऊ । अखिल भारतीय सिविल लेखा (वरिष्ठ लेखाधिकारी) संगठन (AICAOA) के प्रतिनिधिमंडल ने आज लखनऊ में आयोजित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (CCAS) अधिकारियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों एवं मांगों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।संगठन ने आयोग का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि केंद्रीय सिविल लेखा सेवा का ऐतिहासिक रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) संगठन के साथ समान दर्जा एवं वेतन संरचना रही है। इसके अतिरिक्त, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम तथा सप्तम वेतन आयोगों द्वारा विभिन्न लेखा संगठनों के लिए समान वेतनमान एवं सेवा शर्तों की संस्तुति किए जाने के बावजूद केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों के वेतनमान एवं पदानुक्रम में उल्लेखनीय विसंगतियां बनी हुई हैं।प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के समक्ष यह भी रेखांकित किया कि भारत सरकार की समस्त प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेखांकन तथा वित्तीय प्रबंधन की

महत्वपूर्ण जिम्मेदारी केंद्रीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा निभाई जाती है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी इस संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण सेवा को आवश्यक सेवाओं (Essential Services) के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसके बावजूद सेवा की ऐतिहासिक स्थिति एवं महत्व के अनुरूप वेतन एवं कैडर संरचना का संरक्षण नहीं हो पाया है।संगठन ने आयोग से अनुरोध किया कि इन दीर्घकालिक विसंगतियों को दूर करते हुए केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों को उनकी ऐतिहासिक समानता, दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के अनुरूप उचित वेतनमान एवं सेवा स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की जाए।संगठन की ओर से अध्यक्ष श्रीमती गीतांजलि, महासचिव श्री कौशल मिश्रा तथा विधि समिति के अध्यक्ष श्री यू. सी. जोशी ने आयोग के समक्ष अत्यंत सशक्त एवं तथ्यपरक ढंग से पक्ष प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि आयोग केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों की न्यायोचित मांगों पर सकारात्मक विचार करेगा।उल्लेखनीय है कि आठवां केंद्रीय वेतन आयोग 22-23 जून 2026 को लखनऊ में विभिन्न कर्मचारी संगठनों एवं हितधारकों से परामर्श कर रहा है।

Publication Name: Haar Baat
Publication Date: 25/06/2026
Edition: Lucknow
Page No: 4
CCM: 928.04

Demands of Central Civil Accounts Service Officers Presented Before Eighth Pay Commission

आठवें वेतन आयोग के समक्ष केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों की मांगें प्रस्तुत

हरबात संवाददाता

लखनऊ, 23 जून। अखिल भारतीय सिविल लेखा (वरिष्ठ लेखाधिकारी) संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में आयोजित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों और समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। संगठन ने आयोग को अवगत कराया कि केंद्रीय सिविल लेखा सेवा का ऐतिहासिक रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) संगठन के साथ समान दर्जा एवं वेतन संरचना रही है। चतुर्थ, पंचम, षष्ठम तथा सप्तम वेतन आयोगों द्वारा विभिन्न लेखा संगठनों के लिए समान वेतनमान और सेवा शर्तों की संस्तुति किए जाने के बावजूद केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों के वेतनमान एवं पदानुक्रम में आज भी कई विसंगतियां बनी हुई हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि भारत सरकार की समस्त प्राप्तियों और भुगतानों के लेखांकन तथा वित्तीय प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी केंद्रीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा निभाई जाती है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी इस सेवा को आवश्यक सेवाओं (एर२शील्ल३' री१५्री२) की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद सेवा के महत्व और दायित्वों के अनुरूप वेतन एवं कैडर संरचना का संरक्षण नहीं हो सका।

संगठन ने आयोग से मांग की कि केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों को उनकी ऐतिहासिक समानता, जिम्मेदारियों और कार्यभार के अनुरूप उचित वेतनमान एवं सेवा स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की जाए तथा लंबे समय से चली आ रही विसंगतियों को दूर किया जाए।

संगठन की ओर से अध्यक्ष श्रीमती गीतांजलि, महासचिव कौशल मिश्रा तथा विधि समिति के अध्यक्ष यू.सी. जोशी ने आयोग के समक्ष तथ्यपरक एवं प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि आयोग उनकी न्यायोचित मांगों पर सकारात्मक विचार करेगा।

गौरतलब है कि आठवां केंद्रीय वेतन आयोग 22 एवं 23 जून 2026 को लखनऊ में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित कर रहा है।

Publication Name: Prabhat Khabar
Publication Date: 25/06/2026
Edition: Lucknow
Page No: 2
CCM: 1851.01

All India Civil Accounts (Senior Accounts Officer) Organization presented demands of Central Civil Accounts Service officers before the Eighth Pay Commission.

अखिल भारतीय सिविल लेखा (वरिष्ठ लेखाधिकारी) संगठन ने आठवें वेतन आयोग के समक्ष रखीं केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों की मांगें

हिंदी दैनिक भीम वार्ता संवाददाता

लखनऊ। अखिल भारतीय सिविल लेखा (वरिष्ठ लेखाधिकारी) संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने आज लखनऊ में आयोजित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों एवं मांगों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। संगठन ने आयोग का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि केंद्रीय सिविल लेखा सेवा का ऐतिहासिक रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संगठन के साथ समान दर्जा एवं वेतन संरचना रही है। इसके अतिरिक्त, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम तथा सप्तम वेतन आयोगों द्वारा विभिन्न लेखा संगठनों के लिए समान वेतनमान एवं सेवा शर्तों की संस्तुति किए जाने के बावजूद केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों के वेतनमान एवं पदानुक्रम में उल्लेखनीय विसंगतियां बनी हुई हैं। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के समक्ष यह भी रेखांकित किया कि भारत सरकार की समस्त प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेखांकन तथा वित्तीय प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी केंद्रीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा निभाई जाती है। कोविड–19 महामारी के दौरान भी इस संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण सेवा को आवश्यक सेवाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसके बावजूद सेवा की ऐतिहासिक स्थिति एवं महत्व के अनुरूप वेतन एवं कैडर संरचना का संरक्षण नहीं हो पाया है।संगठन ने आयोग से अनुरोध किया कि इन दीर्घकालिक विसंगतियों को दूर करते हुए केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों को उनकी ऐतिहासिक समानता, दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के अनुरूप उचित वेतनमान एवं सेवा स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की जाए। संगठन की ओर से अध्यक्ष श्रीमती गीतांजलि, महासचिव श्री कौशल मिश्रा तथा विधि समिति के अध्यक्ष श्री यू. सी. जोशी ने आयोग के समक्ष अत्यंत सशक्त एवं तथ्यपरक ढंग से पक्ष प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि आयोग केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों की न्यायोचित मांगों पर सकारात्मक विचार करेगा। उल्लेखनीय है कि आठवां केंद्रीय वेतन आयोग 22–23 जून 2026 को लखनऊ में विभिन्न कर्मचारी संगठनों एवं हितधारकों से परामर्श कर रहा है।

Publication Name: Sahara Jeewan
Publication Date: 25/06/2026
Edition: Lucknow
Page No: 8
CCM: 1762.91

All India Civil Accounts (Senior Accounts Officer) Organization presented demands of Central Civil Accounts Service officers before the Eighth Pay Commission

अखिल भारतीय सिविल लेखा (वरिष्ठ लेखाधिकारी) संगठन ने आठवें वेतन आयोग के समक्ष रखीं केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों की मांगें

सहारा जीवन न्यूज़

लखनऊ।अखिल भारतीय सिविल लेखा (वरिष्ठ लेखाधिकारी) संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने आज लखनऊ में आयोजित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों एवं मांगों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।संगठन ने आयोग का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि केंद्रीय सिविल लेखा सेवा का ऐतिहासिक रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संगठन के साथ समान दर्जा एवं वेतन संरचना रही है। इसके अतिरिक्त, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम तथा सप्तम वेतन आयोगों द्वारा विभिन्न लेखा संगठनों के लिए समान वेतनमान एवं सेवा शर्तों की संस्तुति किए जाने के बावजूद केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों के वेतनमान एवं पदानुक्रम में उल्लेखनीय विसंगतियां बनी हुई हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के समक्ष यह भी रेखांकित किया कि भारत सरकार की समस्त प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेखांकन तथा वित्तीय प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी केंद्रीय सिविल लेखा

सेवा के अधिकारियों द्वारा निभाई जाती है। कोविड–19 महामारी के दौरान भी इस संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण सेवा को आवश्यक सेवाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसके बावजूद सेवा की ऐतिहासिक स्थिति एवं महत्व के अनुरूप वेतन एवं कैडर संरचना का संरक्षण नहीं हो पाया है।संगठन ने आयोग से अनुरोध किया कि इन दीर्घकालिक विसंगतियों को दूर करते हुए केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों को उनकी ऐतिहासिक समानता, दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के अनुरूप उचित वेतनमान एवं सेवा स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की जाए।संगठन की ओर से अध्यक्ष श्रीमती गीतांजलि, महासचिव कौशल मिश्रा तथा विधि समिति के अध्यक्ष यू. सी. जोशी ने आयोग के समक्ष अत्यंत सशक्त एवं तथ्यपरक ढंग से पक्ष प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि आयोग केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों की न्यायोचित मांगों पर सकारात्मक विचार करेगा।उल्लेखनीय है कि आठवां केंद्रीय वेतन आयोग 22–23 जून 2026 को लखनऊ में विभिन्न कर्मचारी संगठनों एवं हितधारकों से परामर्श कर रहा है।

Publication Name: Voice of Basti
Publication Date: 25/06/2026
Edition: Lucknow
Page No: 1
CCM: 1053.36

Demands of Central Civil Accounts Service Officers Placed Before Eighth Pay Commission

आठवें वेतन आयोग के समक्ष केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों की मांगें रखीं

वॉयस ऑफ बस्ती संवाददाता

लखनऊ। अखिल भारतीय सिविल लेखा (वरिष्ठ लेखाधिकारी) संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में आयोजित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों और समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। संगठन ने आयोग का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि केंद्रीय सिविल लेखा सेवा का ऐतिहासिक रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संगठन के साथ समान दर्जा एवं वेतन संरचना रही है, लेकिन समय के साथ वेतनमान और पदानुक्रम में कई विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि चतुर्थ, पंचम, षष्ठम एवं सप्तम वेतन आयोगों ने विभिन्न लेखा संगठनों के लिए समान वेतनमान और सेवा शर्तों की संस्तुति की थी, इसके बावजूद केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। संगठन ने कहा कि भारत सरकार की समस्त प्राप्तियों और भुगतानों के लेखांकन तथा वित्तीय प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी केंद्रीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा निभाई जाती है। कोविड–19 महामारी के दौरान भी इस सेवा को आवश्यक सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई थी।

संगठन ने आयोग से अनुरोध किया कि केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों की ऐतिहासिक समानता, दायित्वों और उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए उचित वेतनमान तथा सेवा स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की जाए। संगठन की ओर से अध्यक्ष श्रीमती गीतांजलि, महासचिव कौशल मिश्रा तथा विधि समिति के अध्यक्ष यू.सी. जोशी ने आयोग के समक्ष तथ्यपरक एवं सशक्त पक्ष रखा।

प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास जताया कि आयोग उनकी न्यायोचित मांगों पर सकारात्मक विचार करेगा। उल्लेखनीय है कि आठवां केंद्रीय वेतन आयोग 22 एवं 23 जून 2026 को लखनऊ में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और हितधारकों से परामर्श कर रहा है।